- 20th Year
- Issue: 98
- 06.08.2026 (THURSDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या, समाधान के लिए गंभीर है सरकार-हेमंत सोरेन

रांची, ०५/०८ (संवाददाता): झारखंड के मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सिर्फ राज्य का नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या है। सोरेन ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोरेन का बयान ऐसे समय में आया है, जब विधानसभा के बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आंदोलन तेज हो गया है।

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) सुधार मंच के बैनर तले पांच अन्य लोगों ने मंगलवार रात से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसके साथ ही अनशन पर बैठे लोगों की संज़्या बढ़कर छह हो गई है। सोरेन ने 'एज़्स' पर लिखा, ''मेरे युवा दोस्तों की चिंताएं हमारे लिए बहुत गंभीर मामला है। कथित पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश भर के कई राज्यों के युवाओं के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन गया है। हमारी सरकार इस मामले पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है।'' उन्होंने कहा कि एजेंसियां दिन-रात जांच कर रही हैं और दोषियों को जेल भेजा जा रहा है। सोरेन ने कहा, ''हमारा मकसद सिर्फ जांच करना नहीं, बल्कि अपने युवा दोस्तों को पूरी तरह से समाधान देना है।'' मुज़्यमंत्री ने कहा, ''झारखंड सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं।कोई भी छात्र या अज़्यर्थी, जिसकी कोई मांग या सुझाव हो, वह राज्य सरकार के सामने अपनी बात रख सकता है। उनकी हर बात पूरी गंभीरता से सुनी जाएगी।'' सोरेन ने बताया कि उन्होंने दिन में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भी मुलाकात की और उन्हें छात्रों के प्रदर्शन समेत राज्य के मौजूदा हालात के बारे में अवगत कराया। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए सोरेन ने कहा, ''राज्य की जांच एजेंसियां इस मामले पर पूरी गंभीरता और तेजी से काम कर रही हैं।

कई लोगों को पहले ही गिरज़्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जांच एजेंसियां छापेमारी भी कर रही हैं। मेरा मानना ??है कि आगे चलकर हम ठोस समाधान के लिए कोई फैसला लेंगे।'' यह पूछे जाने पर कि ज़्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कोई बातचीत हुई है, मुज़्यमंत्री ने कहा, ''अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है।

अगर जरूरत पड़ी, तो हम उनसे भी इस मामले पर चर्चा करेंगे।'' झारखंड पीएससी और एसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्र और नौकरी के अज़्यर्थी 25 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, 'लोक भवन' के एक बयान में कहा गया कि मुज़्यमंत्री सोरेन ने भर्ती में कथित अनियमितताओं और छात्रों के हितों को प्राथमिकता देने के मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात की। बयान के मुताबिक, राज्यपाल गंगवार ने परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की जरूरत और युवाओं का भरोसा बनाए रखने के महत्व पर बल दिया।

लोक भवन के बयान के अनुसार, गंगवार ने कथित अनियमितताओं को ''गंभीर चिंता का विषय'' बताया। एक अधिकारी ने बताया कि कथित अनियमितताओं के मामले में झारखंड पुलिस का अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) अब तक 14 लोगों को गिरज़्तार कर चुका है। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच जेपीएससी ने ''अपरिहार्य परिस्थितियों'' का हवाला देते हुए 25 से 27 जुलाई तक प्रस्तावित संयुक्त सिविल सेवा मुज़्य परीक्षा स्थगित कर दी थी। सीआईडी ने 28 जुलाई से अब तक जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांगते से चार बार पूछताछ की है और जांच के सिलसिले में रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद में 18 स्थानों पर छापेमारी भी की है।

झारखंड विस के ७५० मीटर दायरे में सेक्शन १६३ लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक

रांची, ०५/०८ (संवाददाता): झारखंड सरकार ने विधानसभा के बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र से पहले विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह जानकारी बुधवार को एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि यह आदेश छह अगस्त को सुबह आठ बजे से 12 अगस्त को रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, मार्च करने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। कई छात्र संगठनों ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में सात और 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। रांची प्रशासन के एक बयान के अनुसार, छठी झारखंड विधानसभा का छठा (मानसून) सत्र छह अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है।सुरक्षा के नजरिए से सदर, रांची के उप-संभागीय मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है; इसमें झारखंड उच्च न्यायालय (रांची) का इलाका शामिल नहीं है। बयान के अनुसार, निषेधाज्ञा अवधि के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार के हथियार या शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद, लाठी, धनुष-बाण लेकर चलने पर रोक रहेगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक सभा आयोजित करने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

राहुल गांधी युवाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर विभाजन बो रहे-संबित पात्रा

नयी दिल्ली ०५/०८ (संवाददाता): भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर युवाओं का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ''विभाजन के बीज बोने'' और ''झूठा विमर्श'' फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद एवं प्रवक्ता संबित पात्रा ने गांधी पर ''झूठ के पुलिंदे'' को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया और युवाओं से इससे प्रभावित नहीं होने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ''आपके हैं और हम सभी आपके साथ हैं।'' यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी द्वारा गृहमंत्री अमित शाह को हाल में युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए जिज़्मेदार ठहराए जाने के बाद आई। गांधी ने आरोप लगाया था कि शाह में

छात्रों के साथ हुई घटना के बारे में संसद में बताने का साहस नहीं है। गांधी ने यह टिप्पणी उन छात्रों के एक समूह से मुलाकात के बाद की, जिन्होंने पिछले महीने पेपर लीक मामले को लेकर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान कथित पुलिस ज्यादती का सामना किया था। पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा, ''मैंने पहले भी पूरी जिज़्मेदारी के साथ कहा था कि कोई गोली नहीं चलाई गई। चूंकि, यह बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए मैं फिर से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 20 जुलाई के 'संसद चलो' मार्च के दौरान कोई गोली नहीं चलाई गई।'' उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सही नहीं है।'' पात्रा ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उनका इस्तेमाल राजनीति के लिए करना गलत है। उन्होंने कहा, ''युवाओं की कोई गलती नहीं है। जब हम स्कूल और कॉलेज में थे, तब हमने भी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था।'' भाजपा नेता पात्रा ने कहा कि युवाओं को ''निडर'' होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर आंदोलनों में हिस्सा लेने से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी के साथ आज जो बच्चे थे, उनसे मैं स्नेह के साथ कहना चाहता हूं—निडर रहिए और बिल्कुल मत डरिए। हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आप हमारे अपने हैं।

प्रधानमंत्री आपके हैं और हम सभी आपके साथ हैं।'' पात्रा ने आरोप लगाया कि गांधी युवाओं का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए ''झूठा विमर्श'' तैयार कर रहे हैं और ''विभाजन के बीज बो रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि गांधी दूसरों के कंधों का इस्तेमाल करके राजनीतिक विमर्श खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।

पुरानी गाड़ियों के लिए भी सुरक्षित है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, घबराने की जरूरत नहीं-गडकरी

नयी दिल्ली ०५/०८ (संवाददाता): केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद को बताया है कि श्व20 पेट्रोल पुरानी गाड़ियों के लिए सुरक्षित है -इनमें वे गाड़ियां भी शामिल हैं जो श्व20 कज़्पैटिबिलिटी स्टैंडर्ड लागू होने से पहले बनी थीं -और इससे गाड़ियों में कोई असामान्य टूट-फूट या परफॉर्मेंस से जुड़ी बड़ी समस्या नहीं होती है। हालांकि, उन्होंने माना कि इथेनॉल का ज़्यादा मिश्रण होने से ज़्यूल एफिशिएंसी 2 से 6 प्रतिशत तक कम हो सकती है। गडकरी, सांसद कॉन्स्टैन्टाइन रवींद्रन के सवाल का जवाब दे रहे थे। रवींद्रन ने देश भर में इ20 पेट्रोल उपलज़्ध होने का

पुरानी गाड़ियों पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसमें 1 अप्रैल 2017 से पहले बनी और रजिस्टर हुई BS-III मॉडल की गाड़ियां भी शामिल थीं।

मंत्री ने कहा कि सरकार को वाहन निर्माताओं, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन या उपभोक्ता संगठनों से इ20 पेट्रोल को इंजन खराब होने, ज़्यूल-पंप की समस्याओं, जंग लगने, पानी की मिलावट या परफॉर्मेंस से जुड़ी अन्य दिक्कतों से जोड़ने वाली कोई व्यापक या पुज़्ता शिकायत नहीं मिली है। लैब स्टडी और फील्ड ट्रायल का हवाला देते हुए, गडकरी ने कहा कि इ20 पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद पुरानी या लेगेसी गाड़ियों में कोई असामान्य टूट-फूट या परफॉर्मेंस में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। ये स्टडी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया, सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पेट्रोलियम और ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने की थीं। इन ट्रायल में इंजन की ड्यूरेबिलिटी, चलाने में आसानी, स्टार्ट होने की क्षमता, जंग से बचाव, मटीरियल की कज़्पैटिबिलिटी और एमिशन की जांच की गई। गडकरी के मुताबिक, नतीजों से यह साबित हुआ कि तय मानकों के अनुसार इस्तेमाल करने पर इ20 पेट्रोल सुरक्षित है।

छात्रों से मिले बाबूलाल मरांडी, कहा-भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है सरकार

रांची ०५/०८ (संवाददाता): झारखंड में परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और धांधली के विरोध में छात्रों का आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। राज्य में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की, जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कल विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। कई दिनों से छात्र विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी मिले हैं। हम सभी को लगता है कि ये सिर्फ़ गड़बड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि झारखंड में नौकरियों की बिक्री हो रही है। इसके पर्याप्त सबूत भी मौजूद हैं। मरांडी ने दावा किया कि आज सर्वदलीय बैठक में भी मैंने साफ़ कहा कि इन गड़बड़ियों को देखते हुए सरकार

को परीक्षाएँ रद्द कर देनी चाहिए। इस पूरे मामले की जाँच ष्टक्चढ्ढ से कराई जानी चाहिए। स्पीकर ने कहा है कि इस पर बैठक में चर्चा होगी और फिर कोई फ़ैसला लिया जाएगा। छात्रों की माँग जायज़ है। हमारी पार्टी झारखंड के छात्रों की माँगों के साथ पूरी तरह खड़ी है। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि विधानसभा का सत्र कल, 6 अगस्त से शुरू हो रहा है। आज शाम 6 बजे ह्रश्व विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक से पहले, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सभी क्चछ्वक्क-ह्रश्व विधायक छात्रों से मिलने यहां आए। वे यहां विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि हमने उनकी बात सुनी, उन्होंने हमसे विस्तार से बात की। यह सिर्फ़ पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि %नौकरी फिज़्स% करने का मामला है। राज्य सरकार के इशारे पर और ष्टरूहेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहां नौकरियां बेची जा रही हैं। इसलिए, वे मांग कर रहे हैं कि छ्वस्स्ष्ट 14वीं परीक्षा रद्द की जाए।

संसद में गतिरोध जारी, राहुल गांधी से मिले किरेन रिजिजु

नयी दिल्ली ०५/०८ (संवाददाता): बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज भी विपक्ष ने संसद में अपना विरोध जारी रखा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया और कांग्रेस, सीपीआई और समाजवादी पार्टी पर राम मंदिर चंदा घोटाले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। बैंकर्स बुज़्स एविडेंस बिल, 2026 लोकसभा में बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित हो गया। वहीं, संसद ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संज़्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाले विधेयक को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्यसभा ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संज़्या) संशोधन विधेयक, 2026 को चर्चा के बाद

ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।

राज्यसभा में बुधवार को अन्नाद्रमुक के नेता डा. एम थंबीदुरै ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसज़्मति से पारित किया था। राज्यसभा में बुधवार को भाजपा के सतपाल शर्मा ने जज़्मू कश्मीर से आज ही के दिन अनुच्छेद 370 हटाये जाने का जिक्र करते हुए दावा किया कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वह देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतपाल शर्मा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार जज़्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग दशकों से कर रहे थे। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा में कुछ ज्यादा काम नहीं हो सका और प्रश्नकाल एवं शून्यकाल नहीं चल सके। वे अयोध्या में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। राज्यसभा में भी यही हंगामा देखने को मिला। संसद के दोनों सदनों में जारी गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि संसद भवन परिसर में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के दौरान संसद की कार्यवाही में बने गतिरोध को समाप्त करने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकारी सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के संसद में बोलने की उज़्मीद है, जब विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026% पर चर्चा और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। यह तब हो रहा है जब विपक्ष सदन में उनकी गैर-मौजूदगी को लेकर आलोचना कर रहा है।

विविध समाचार

मोहन भागवत के जेन जी संवाद पर अभिजीत दिपके का बयान, युवाओं को मिलना चाहिए नेतृत्व

छत्रपति संभाजीनगर ०५/०८ (संवाददाता): कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को कहा कि युवाओं के साथ संवाद का स्वागत है, लेकिन अगर इसका नेतृत्व युवा या 'जेन जेड' के प्रतिनिधि करें तो यह और भी बेहतर होगा। उन्होंने यह टिप्पणी मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत और छात्रों के बीच प्रस्तावित संवाद से पहले की। भागवत छह अगस्त को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जेन अल्फा और जेन जेड के छात्रों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देशभर के 100 से अधिक शहरों के 15 से 19 वर्ष की आयु के 2,000 से अधिक छात्र एकत्र होंगे।

वर्ष 1997 से 2012 के दौरान जन्मे युवाओं को जेन जेड , जबकि 2013 से 2024 के बीच जन्मे बच्चों को जेन अल्फा कहा जाता है। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए युवा प्रदर्शनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मुंबई में भागवत के आगामी कार्यक्रम के बारे में पूछे जाने पर दीपके ने कहा, ''यह अच्छी बात है कि संवाद हो रहा है, लेकिन अगर इसके लिए कुछ युवा चेहरों को आगे किया जाए तो यह और भी बेहतर होगा।'' उन्होंने कहा, ''युवाओं ने ऐसा करने पर मजबूर किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करनी पड़ रही है और मोहन भागवत भी जेन जेड के साथ बातचीत करना चाहते हैं।'' कॉजपा संस्थापक ने छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से कहा, ''भले देर से ही सही, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया है कि जेन जेड को नजरअंदाज या खारिज नहीं किया जा सकता और हमें उनसे बात करनी चाहिए। ये युवा ही देश का भविष्य हैं।

दीपके ने इस बात पर जोर दिया कि जेन जेड को युवा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ''लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर (युवाओं से बातचीत करने वाले) चेहरे जेन जेड या युवा हों तो यह और भी बेहतर होगा। अगर 70-80 साल की उम्र के लोग बात कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन इससे जेन जेड को ज़्या मिलेगा?

जेन जेड को युवा प्रतिनिधित्व की जरूरत है। अगर युवा, युवाओं से बात करेंगे तो यह और बेहतर होगा।'' उन्होंने यह भी दावा किया कि झारखंड सरकार वहां आंदोलन कर रहे छात्रों की अनदेखी कर रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित प्रश्नपत्र लीक को लेकर छात्र 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

दीपके ने बताया कि उन्होंने झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा, ''उन्हें अपने तंबू लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उनके लिए शौचालय की सुविधा भी नहीं है। झारखंड में उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है जैसा जंतर-मंतर (पिछले महीने नयी दिल्ली में) पर हमारे साथ किया गया था, लेकिन हम झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के साथ हैं।

दिल्ली पुलिस ने विशेष प्रकोष्ठ से अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़

नयी दिल्ली ०५/०८ (संवाददाता): दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने एक अंतरराज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आठ कथित तस्करों को गिरज़्तार किया है और उनके पास 18 पिस्तौलें और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यहां बताया कि आरोपी मध्य प्रदेश और उज़्र प्रदेश से अर्धस्वचालित पिस्तौल और देसी तमंचे खरीदकर दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों के अपराधियों को बेचने वाले गिरोह से जुड़े हैं। विशेष प्रकोष्ठ में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) एन. चैतन्य ने बताया कि आरोपियों की पहचान हरीश चंद्र (24), प्रीतपाल सिंह (24), शीशपाल सिंह उर्फ यश चौधरी (26), कुलदीप सागर (20), अगेश कुमार (25), नूर मोहज़्मद उर्फ तसलीम (36), मोहज़्मद शान (19) और विक्रम सिंह (36) के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि गिरोह के सदस्य तस्करों और खरीदारों के साथ समन्वय करने के लिए सोशल मीडिया ऐप, 'वर्चुअल नंबर' और ऑनलाइन फर्जी पहचान का इस्तेमाल करते थे। डीसीपी ने एक बयान में बताया कि दिल्ली-एनसीआर में अवैध हथियारों की तस्करी की गुप्त सूचना पर कई हज़्तों तक काम किया गया जिसके बाद आरोपियों को पकड़ कर उनके पास से पिस्तौलें बरामद की गईं। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस ने 12 अर्धस्वचालित पिस्तौल, पांच देसी तमंचे, एक रिवॉल्वर, 10 अतिरिक्त मैगज़ीन, पांच नौ एमएम के प्रतिबंधित कारतूस, एक अन्य कैलिबर का कारतूस और एक दरांती बरामद की।

डीसीपी ने कहा कि जांच पांच जुलाई को शुरू हुई जब हरीश चंद्र को मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाई गई आठ अर्ध स्वचालित पिस्तौल और आठ मैगजीन के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान, उसने खुलासा किया कि वह और उसका भाई गिरोह के कथित सरगना शीशपाल सिंह के निर्देश पर अवैध हथियारों को ले जा रहे थे। उसके खुलासे के आधार पर, पुलिस ने प्रीतपाल सिंह को गिरज़्तार कर लिया और बाद में हरियाणा के बल्लभगढ़ से शीशपाल को भी पकड़ लिया गया और उसके किराए के आवास से एक और अवैध पिस्तौल बरामद की।

पुलिस के अनुसार, शीशपाल लगभग तीन वर्षों से अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल था और उसने कई राज्यों में अपना एक नेटवर्क बनाया था जिसमें हथियारों की आपूर्ति करने वाले, तस्कर व उन्हें ले जाने वाले लोग शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि 15 जुलाई को विक्रम सिंह को गिरज़्तार किया गया और उसके घर से नौ एमएम के पांच कारतूस बरामद हुए। इसी तरह अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया और उनके पास भी हथियार बरामद हुए।

केरल के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त

तिरुवनंतपुरम ०५/०८ (संवाददाता):केरल के कई हिस्सों में बुधवार को मूसलाधार बारिश जारी रही, जिससे बड़े पैमाने पर जलभराव हो गया और सड़कें जलमग्न हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि और अधिक राहत शिविर खोले गए हैं तथा निचले इलाकों के निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

पज़नमथिट्ठा, अलाप्पुझा और कोट्टयम के दक्षिणी जिलों में बारिश का कहर जारी रहा, जहां लगातार हो रही बौछारों के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया।इन जिलों के कई जलमग्न इलाकों में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को घुटने तक भरे पानी से होकर जाते देखा गया। कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरा रहने और कई घरों में पानी जमा रहने के कारण और भी अधिक निवासियों को राहत शिविरों में ले जाया गया। अधिकारियों ने कहा कि भारी बारिश जारी रहने के मद्देनजर सुरक्षित निकाले गए लोगों को ठहराने के लिए अतिरिक्त राहत शिविर बनाए गए हैं। कोझिकोड और कन्नूर के उच्च पहाड़ी इलाकों सहित उज़्री जिलों के कई हिस्सों में भी व्यापक वर्षा दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने केरल के पांच जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) ने राज्य के दक्षिणी तट के कुछ हिस्सों में ऊंची लहरें उठने और तटवर्ती इलाकों में समुद्र का पानी घुसने की चेतावनी दी है। आईएमडी ने पज़नमथिट्ठा, कोट्टयम, इडुक्की, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि बृहस्पतिवार को यह अलर्ट पज़नमथिट्ठा, अलाप्पुझा, कोट्टयम, इडुक्की, एर्नाकुलम, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए लागू रहेगा।

आईएमडी ने बताया कि शुक्रवार के लिए मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम एजेंसी के अनुसार, राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि छह और सात अगस्त को चुनिंदा स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की उज़्मीद है। आईएनसीओ आईएस ने कल्लाक्कडाल नामक समुद्री स्थिति को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें समुद्र में अचानक ऊंची और उग्र लहरें उठती हैं, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है।

कल्लाक्कडाल समुद्र की एक ऐसी स्थिति है जिसमें बिना किसी स्थानीय तूफान या हवा के अचानक समुद्र में बहुत ऊंची और उग्र लहरें उठने लगती हैं और तटों पर बाढ़ आ जाती है। यह चेतावनी तिरुवनंतपुरम जिले में कप्पिल से पोझियूर, कोल्लम जिले में अलप्पड से एडवा, और अलाप्पुझा जिले में चेल्लानम से अझिक्कल जेट्टी तक के तटीय पट्टी के लिए जारी की गई है।

आईएनसीओआईएस ने बृहस्पतिवार दोपहर 2.30 बजे तक कन्याकुमारी तट पर 1.2 मीटर से 1.6 मीटर तक ऊंची लहरें उठने और समुद्र के पानी के अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करने की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने मछुआरों, तटीय निवासियों और आम जनता को सतर्क रहने तथा चेतावनी की अवधि के दौरान संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है। इन चेतावनियों के मद्देनजर, केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) ने मछुआरों और तटीय निवासियों को सतर्क रहने, आईएनसीओआईएस की चेतावनी वापस लिये जाने तक समुद्र तटों तथा पर्यटन गतिविधियों से दूर रहने और संभावित रूप से तटों की मिट्टी बहने के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी है।

लगातार हो रही बारिश के बीच, केएसडीएमए ने भूस्खलन, पहाड़ों से मलबे एवं कीचड़ के बहाव और अचानक आने वाली बाढ़ के प्रति संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से दिन के समय सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। प्राधिकरण ने बाढ़ की आशंका वाले निचले इलाकों के निवासियों को स्थानीय स्थिति का आकलन करने के बाद राहत शिविरों में जाने की सलाह भी दी है। लोगों को भारी बारिश के दौरान नहाने, मछली पकड़ने या किसी अन्य उद्देश्य से नदियों और अन्य जल स्रोतों में न जाने की सलाह दी गई है।

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम की चेतावनी वापस लिये जाने तक झरनों, जलाशयों और पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर जाने से बचें।

प्राधिकरण ने वाहन चालकों को पानी के स्रोतों के पास की सड़कों और मरज़्मत के काम से गुजरने वाले रास्तों पर यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है, ज़्योंकि भारी बारिश के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे नजारों को देखने या सेल्फी लेने के लिए नदियों या जल निकायों के ऊपर बने पुलों पर इकट्ठा न हों, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के समय यात्रा करने से बचना चाहिए।

दिल्ली में राहुल गांधी ने पूछा कि छात्रों को माफ करने का अधिकार प्रमं को किसने दिया

नयी दिल्ली,०५/०८ (संवाददाता): कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की 'गुमराह युवाओं को माफ करने'' संबंधी टिप्पणी को लेकर मंगलवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि 'भारत के भविष्य' को माफ करने का अधिकार प्रधानमंत्री को किसने दिया? उन्होंने एमडीएमके नेता वाइको की पुस्तक 'वाइको इन पार्लियामेंट' के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सोच भारत की विविध भाषाओं, संस्कृतियों और इतिहास को कमजोर करने वाली है तथा इसी के विरोध में छात्र सड़कों पर उतरकर ''भारत की अवधारणा'' (आइडिया ऑफ इंडिया) की रक्षा कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां छात्र रोजगार, निष्पक्ष परीक्षाओं और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर सड़कों पर हैं।

उनका कहना था कि एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उन्हें माफ करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, ''उन्हें छात्रों को माफ करने का अधिकार किसने दिया? भारत के भविष्य को माफ करने का अधिकार उन्हें कहां से मिलता है?'' कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए।

राहुल गांधी ने वाइको के राजनीतिक संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के प्रत्येक राज्य को अपनी संस्कृति, इतिहास और के साथ सज़्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग तमिल, मराठी, बांग्ला, मलयालम समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं और उनसे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को महत्व नहीं देते हुए केवल आरएसएस द्वारा परिभाषित इतिहास और को ही प्रासंगिक मानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, उनके सहयोगियों और आरएसएस की सोच के पीछे एक ''खतरनाक और विभाजनकारी'' विचार है।

उनके अनुसार, यह विचार भारत की विविध पहचान, भाषाओं और इतिहास को महत्वहीन मानता है, जबकि भारत ऐसा कभी स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र इसी कारण सड़कों पर हैं और वे अपने-अपने तरीके से भारत की विविध संस्कृति, भाषाओं और इतिहास की रक्षा कर रहे हैं।

फारूक अज़्दुल्ला ने 5 अगस्त 2019 को लोकतंत्र का काला दिन बताया, राज्य का दर्जा बहाली की मांग की

श्रीनगर,०५/०८ (संवाददाता): नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अज़्दुल्ला ने पांच अगस्त, 2019 के दिन को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले दिनों में एक बताते हुए बुधवार को कहा कि उस दिन लिए गए निर्णयों ने जज़्मू-कश्मीर से उसकी संवैधानिक गारंटी, राजनीतिक पहचान और राज्य का दर्जा छीन लिया। अज़्दुल्ला ने एक बयान में कहा कि जज़्मू-कश्मीर के लोगों ने पांच अगस्त, 2019 के फैसलों को पहले दिन से ही नकार दिया और वे इन ''एकतरफा और असंवैधानिक कदमों'' के खिलाफ मजबूती से डटे हुए हैं। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था।

नेकां प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी जज़्मू कश्मीर की संवैधानिक गारंटियों, लोकतांत्रिक अधिकारों और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपना शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगी। अज़्दुल्ला ने कहा कि नेकां के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहराया है कि वह विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके पांच अगस्त के फैसलों को खारिज करेगी तथा जज़्मू कश्मीर के संवैधानिक दर्जे और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को अपनी पहली विधायी प्राथमिकता बनाएगी।

उदयनिधि की गिरफ्तारी पर भड़के एकके स्टालिन, टीवीके सरकार को घेरा, अहंकार से बर्बादी तय

चेन्नई ०५/०८ (संवाददाता): सोमवार को तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर तेज़ी आ गई, जब ष्ठरूय्य अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कावेरी जल विवाद और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरज़्तारी को लेकर मुज़्यमंत्री विजय और सज़्ाधारी %तमिलगा वेट्री कझगम% (ञ्जङ्कय्) सरकार पर तीखा हमला बोला। स्टालिन ने सरकार पर तमिलनाडु के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ञ्जङ्कय् सरकार कावेरी नदी पर राज्य के अधिकार सुरक्षित करने और कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध प्रोजेज़्ट का विरोध करने में अपनी नाकामी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है।स्टालिन ने कहा कि तंजावुर में ष्ठरूय्य के विरोध प्रदर्शन में लोगों की भारी भागीदारी, कावेरी मुद्दे पर सरकार के अहंकारी और उदासीनरवैये के खिलाफ तमिलनाडु के किसानों और आम लोगों में बढ़ते गुस्से को दिखाती है। उनके अनुसार, पानी के विवाद को लेकर सरकार के तौर-तरीकों से अपनी निराशा जाहिर करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता, किसान और आम जनता बड़ी संज़्या में प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन ने कावेरी जल बंटवारे पर अपने दावों को मजबूती से न रख पाने और मेकेदातु बांध प्रस्ताव का विरोध न कर पाने की राज्य सरकार की नाकामी को लेकर फैली चिंताओं को उजागर किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान उदयनिधि स्टालिन के भाषण का ज़िक्र करते हुए, ष्ठरूय्य प्रमुख ने कहा कि विपक्ष के नेता ने सरकार की प्रशासनिक नाकामियों को सबके सामने उजागर किया है। अपने भाषण में उदयनिधि ने आरोप लगाया था, अक्षम और कठपुतली मुज़्यमंत्री न तो कावेरी का पानी ला पाए हैं और न ही मेकेदातु बांध को रोकने के लिए आवाज़ उठा पाए हैं। किसान दुख में आँसू बहा रहे हैं, जबकि मंत्री मुज़्यमंत्री की फ़िल्म देखकर आँसू बहा रहे हैं। तमिलनाडु में एक जोकर कैबिनेट सज़्ा में है। स्टालिन ने दावा किया कि मौजूदा सरकार अब तक इन आरोपों का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई है। DMK प्रमुख ने आरोप लगाया कि TVK सरकार ने कावेरी विवाद से ध्यान भटकाने के लिए उदयनिधि स्टालिन की गिरज़्तारी की साजिश रची। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी उदयनिधि के घर पहुंची और उन्हें हिरासत में लेकर तंजावुर ले गई। स्टालिन के मुताबिक, विपक्ष के नेता के लिए ज़मानत पाना मुश्किल बनाने के लिए कई आपराधिक धाराएं लगाई गईं। स्टालिन ने यह भी सवाल उठाया कि उदयनिधि को तंजावुर ज़्यों ले जाया गया, जबकि उनके अनुसार, पूछताछ चेन्नई में ही की जा सकती थी।

विविध समाचार

शिवजी को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक

श्रावण माह 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा। इस माह में कई व्रत-त्योहार, जैसे नाग पंचमी, रक्षाबंधन व सावन शिवरात्रि मनाए जाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार शिव आराधना का पावन श्रावण माह इस बार 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगा। पूरे माह शिव उपासकों को लगातार पूजा-अर्चना का अवसर मिलेगा। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने की पूरी संभावना है। मंदिरों में विशेष आयोजन शुरू हो चुके हैं।

शास्त्रों में मिलता है रुद्राभिषेक का वर्णन

श्रावण माह में शिवजी का रुद्राभिषेक करने से जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही कोई बड़ी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे परिवार पर हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि रुद्राभिषेक करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, इससे सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। यदि आप सावन शिवरात्रि, सावन सोमवार या सावन प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक विधि-विधान से करेंगे, तो आपको चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे। शास्त्रों में रुद्राभिषेक को शिव जी को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय बताया गया है भगवान शंकर के प्रिय माह सावन में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से कई विपदाओं से मुक्ति मिलती है। रुद्राभिषेक करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी रुद्राभिषेक का वर्णन किया गया है। रुद्राभिषेक करने से घर में शांति बनी रहती है और ग्रहों का बुरा प्रभाव भी कम होता है।

सावन का महत्व

हिंदू धर्म में सावन माह को भक्ति, व्रत, और साधना का महिना माना जाता है। मान्यता है कि इस समय सृष्टि का संचालन स्वयं भगवान शिव करते हैं। इस दौरान भक्त सोमवार का व्रत, रुद्राभिषेक, और शिवपुराण पाठ करते हैं। विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं द्वारा किए गए सोमवार व्रत को विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने वाला और मनचाहा जीवनसाथी पाने वाला व्रत माना गया है। इस पावन अवसर पर शिव मंदिरों में विशेष सजावट, जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और रात्रि जागरण जैसे कार्यक्रमों की तैयारियां भी जोरों पर हैं।

सावन महीने के हर मंगलवार को रखा जाता है मंगला गौरी व्रत

मंगला गौरी व्रत सावन महीने के हर मंगलवार को रखा जाता है और यह देवी पार्वती जिनका एक नाम गौरी भी है, उन्हें समर्पित है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए रखती हैं। वहीं, अविवाहित लड़कियां मनपसंद जीवनसाथी और शीघ्र विवाह के लिए यह व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगला गौरी व्रत रखने से कुंडली में मंगल दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है।

मंगला गौरी व्रत का महत्व

- मंगला गौरी व्रत रखने से विवाहित महिलाओं के वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है। इस व्रत को रखने से पति को लंबी आयु मिलती है और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
- ऐसी मान्यता है कि देवी पार्वती जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, इस व्रत को करने वाली सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है।
- यह पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम, समझ और तालमेल को बढ़ाता है जिससे गृहस्थी खुशहाल रहती है। अविवाहित कन्याओं के लिए मंगला गौरी व्रत शीघ्र विवाह और मनपसंद जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है।
- जो लड़कियां योग्य वर की तलाश में हैं या विवाह में किसी प्रकार की बाधा का सामना कर रही हैं उन्हें यह व्रत पूरी श्रद्धा से करने की सलाह दी जाती है। देवी पार्वती की कृपा से उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें सुयोग्य जीवनसाथी मिलता है जो उनके जीवन को सुखमय बनाता है।
- मंगला गौरी व्रत कुंडली में मंगल दोष के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक होता है। मंगल दोष के कारण विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में समस्याएं या अन्य कष्ट आ सकते हैं।
- इस व्रत को करने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं, जिससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह व्यक्ति को साहस और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है।
- जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, उनके लिए भी मंगला गौरी व्रत लाभकारी माना जाता है। देवी पार्वती को मातृत्व और सृजन की देवी माना जाता है।
- इस व्रत को सच्चे मन से करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख की प्राप्ति में मदद मिलती है। यह व्रत संतान के स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए भी शुभ फलदायी होता है।

आखिर क्यों भगवान शिव को कहा जाता है महाकाल

सावन का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में हर तरफ आप भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते हुए लोगों को देखती होंगी। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। उन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, शंभू, आदि नामों से पुकारा जाता है, लेकिन आखिर क्यों उन्हें महाकाल पुकारा जाता है?

आखिर भगवान शिव को यह नाम क्यों मिला?

पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन में एक शिव भक्त ब्राह्मण निवास करता था। यहां पर रहने वाले लोग दूषण नाम के राक्षस के प्रकोप से डरते थे। लोग उसे काल के नाम से जानते थे। ब्रह्मा जी से दूषण को कई शक्तियां मिली थी, जिनका दुरुपयोग कर वह निर्दोष लोगों को परेशान करता था। राक्षस की शक्तियों के प्रकोप से ब्राह्मण काफी दुखी था, उसने भगवान शिव से राक्षस के नाश की प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने काफी वक्त तक कुछ नहीं किया। प्रार्थनाओं का असर न होता देख एक दिन ब्रह्म भगवान शिव से नाराज हो गए और उनका पूजन बंद कर दिया। अपने ब्राह्मण भक्त को दुखी देख भगवान शिव हुंकार के रूप में प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया। क्योंकि लोग दूषण को काल कहते थे, इसलिए उसके वध के कारण भगवान शिव का नाम महाकाल पड़ा।

क्या होता है महाकाल का मतलब?

काल का मतलब होता है समय और महाकाल का मतलब हुआ है वह जो समय से परे है अथवा उसका नियंत्रणकर्ता है। मान्यताओं के अनुसार, शिव जी प्रलय, विघटन या मृत्यु के देव है और वह हमारे समय यानी काल को भी नियंत्रित करते है।

महाकाल की पूजा

राक्षस का वध करने के कारण बाबा महाकाल की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा महाकाल की आराधना करता है, उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता है।

सावन में कांवड़ का है विशेष महत्व, कितने तरह की होती है ये यात्रा

सावन मास के प्रारंभ होने के साथ-साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। कांवड़ यात्रा में कांवड़िया गंगा नदी में स्नान कर लौटते में जल भरकर से शिव मंदिर में सावन शिवरात्रि के दिन अभिषेक करते हैं। कांवड़िया भगवान शिव से प्रार्थना कर आशीर्वाद मांगते हैं, इस कांवड़ यात्रा को लेकर यह मान्यता है कि भगवान शिव कांवड़िया की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं।

कितने प्रकार की होती है कांवड़ यात्रा

सामान्य कांवड़ यात्रा

सामान्य कांवड़ यात्रा में शिव भक्त चलते-चलते जब थक जाते है तो बीच-बीच में आराम कर सकते हैं। आराम के दौरान कांवड़ियों को इस बात का खास ध्यान देना पड़ता है कि कांवड़ बीच में जमीन पर न रखें। कांवड़िया अपने साथ स्टैंड लेकर चलते हैं, साथ ही वे कांवड़ को किसी पेड़ की डाल पर भी टांग देते हैं।

डाक कांवड़ यात्रा

डाक कांवड़ यात्रा में कांवड़िया विश्राम नहीं करता है। जब वह पवित्र नदी से स्नान कर जल भरता है तब वह सीधा मंदिर में जाकर रुकता है। डाक कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़िया बीच में किसी भी चीज के लिए नहीं रुकते और उनकी यात्रा को सरल बनाने के लिए मार्ग में कई तरह की उचित व्यवस्था की जाती है।

खड़ी कांवड़ यात्रा

खड़ी कांवड़ यात्रा में साधक कांवड़ लेकर चलते है। इस खड़ी कांवड़ यात्रा में 2-3 लोग साथ में चलते है, जिसमें एक के थकने पर दूसरे लोग कांवड़ लेकर साधक की यात्रा पूरी करने में सहायता करते हैं।

दांडी कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा के सभी प्रकारों में दांडी कांवड़ यात्रा सबसे कठिन मानी गई है। इस दांडी कांवड़ यात्रा में कांवड़िया पवित्र नदी से स्नान कर जल भरता है और मंदिर तक दंडवती करते हुए पहुंचता है। इस यात्रा में सबसे ज्यादा समय लगता है।

कौन सी कांवड़ यात्रा है सबसे सरल और सबसे कठिन

सबसे सरल की बात करें तो सामान्य कांवड़ यात्रा सबसे सरल है। इस यात्रा में कांवड़िया बीच-बीच में कांवड़ को स्टैंड पर रखकर आराम कर सकता है। वहीं दांडी कांवड़िया कांवड़ यात्रा के सभी प्रकार में सबसे ज्यादा कठिन है। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़िया दंडवती करते हुए भगवान शिव को कांवड़ का जल अर्पित करता है।

यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन में क्यों नहीं रखना चाहिए?

सावन मास में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है, इस माह में कांवड़िया कांवड़ में जल भरकर शिव जी का अभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कांवड़ को जमीन पर क्यों नहीं रखते? कांवड़ को जमीन में नहीं रखने के पीछे एक धार्मिक मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार कांवड़ियों का मानना है कि कांवड़ भगवान शिव का स्वरूप है, जिसे कभी भी जमीन में रखकर उसका अपमान नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा कांवड़ में भरा हुआ जल भगवान शिव को चढ़ता है, ऐसे में कांवड़िया जमीन पर रखे हुए जल को भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाते है। जिस मार्ग में कांवड़िया विश्राम के लिए रुकते है, उस स्थान में कांवड़िया स्टैंड या पेड़ पर कांवड़ को रखते है, ताकि कांवड़ जमीन को स्पर्श न हो।

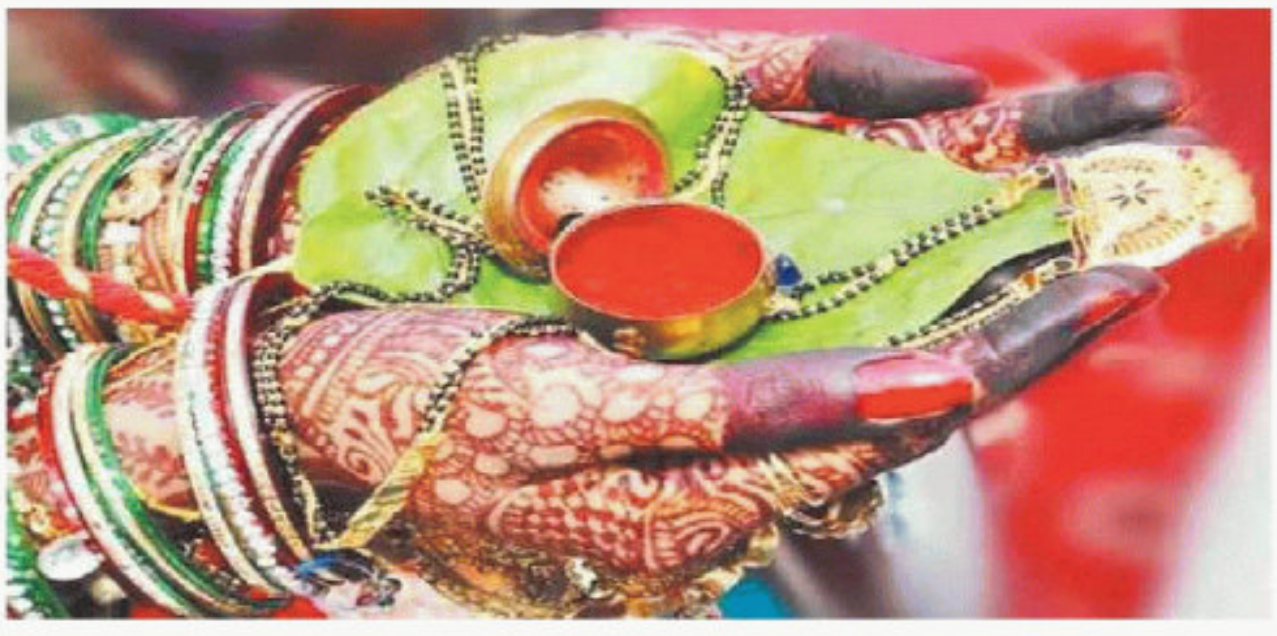

सावन के मंगला गौरी व्रत के दिन महिलाएं जरूर करें इन चीजों का दान

सनातन धर्म में मंगला गौरी का व्रत माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से दान-पुण्य करने का विधान है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि किन चीजों का दान करने से लाभ हो सकता है।

हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव के साथ-साथ माता पार्वती को समर्पित होता है। इस पवित्र महीने के दौरान पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए किया जाता है।

कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। अब ऐसे में जो महिलाएं इस दिन दान-पुण्य कर रही है, उन्हें किन चीजों का दान करने से लाभ हो सकता है।

करें हरी चूड़ियों का दान

मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। चूड़ियां सुहाग का प्रतीक होती है और इनका दान करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, जिससे सुहागिनों को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि मंगला गौरी व्रत के दिन सुहागिन महिला को चूड़ियों का दान करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, शांति और मधुरता आती है। पति-पत्नी के बीच के कलेश दूर होते हैं और संबंध मजबूत होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, उनके लिए भी मंगला गौरी व्रत और इस दिन सुहाग की वस्तुओं, विशेषकर चूड़ियों का दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे मंगल दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं।

काजल का दान

ज्योतिष शास्त्र में काजल को बुरी नजर से बचाने वाला और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने वाला माना गया है। मंगला गौरी व्रत के दिन काजल का दान करने से वैवाहिक जीवन को लगी बुरी नजर उतर जाती है और दांपत्य जीवन में नकारात्मकता भी नष्ट होने लगती है। मंगला गौरी व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है।

मसूर की दाल का दान

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल गौरी व्रत मंगल ग्रह से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए रखा जाता है। मसूर की दाल का संबंध मंगल ग्रह से होता है, और इसे दान करने से कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है, जिससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, उनके विवाह में बाधाएं आती है या वैवाहिक जीवन में परेशानियां रहती हैं।
मंगला गौरी व्रत के दिन मसूर की दाल का दान करने से इस दोष का प्रभाव कम होता है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है।

कलिंग समाचार

गुरूवार 06 अगस्त 2026

नयी धड़कन जगाती तस्वीरें

पेपर लीक पर समय रहते कार्रवाई न करने और अपना दंभ न छोड़ने की बड़ी भारी कीमत नरेन्द्र मोदी और भाजपा को चुकानी पड़ सकती है, यह देश का मौजूदा माहौल बता रहा है। जंतर-मंतर पर आंदोलन कारियों पर लाठियां बरसाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना सरकार का गलत फैसला था और अब इसमें एक बड़ी साजिश भी दिखाई दे रही है कि पुलिस की वर्दी में आए गुंडों ने आंदोलनकारियों का दमन किया। बहुत सी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें नजर पुलिस की क्रूरता नजर आ रही है। अब मामला अदालत तक पहुंच चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई चीफ जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने की। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को 4 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा/जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और अन्य रिकॉर्ड से छेड़छाड़ न करने और उन्हें पूरी तरह संरक्षित रखने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की गई है। लेकिन इससे पहले जनता की अदालत में नरेन्द्र मोदी के 12 सालों पर सुनवाई शुरु हो चुकी है। जंतर-मंतर से जो छवियां आ रही हैं, उनमें नजर आ रहा है कि मामला अब केवल धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार तक सीमित नहीं है। लोग हर उस बात पर शिकायत कर रहे हैं, जिनके कारण देश की दुर्दशा हुई है। हमारे पास जॉब नहीं है, आज भगा दो, कल फिर आएंगे, ऐसे पोस्टर्स, मेलोनी के हाथ के बने समोसे ले लो जैसे तंज, यह कहना कि जब राघव चड्ढा बिक सकता है तो फिर मीडिया तो मीडिया है, हनुमान चालीसा बजा कर उस पर थिरकना, उसमें मुस्लिमों का भी साथ आना, हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे युवक को पुलिस ने उठा कर पटका तो उसने फौरन उठकर तिरंगा लहराया, ऐसे हजारों-हजार दृश्य भाजपा के खोखले राष्ट्रवाद, हिंदू-मुसलमान जैसे एजेंडे को मटियामेट कर रहे हैं। मोदी की विदेश यात्राओं से लेकर विपक्षी दलों के लोगों को तोड़ने तक सारी रणनीतियों का जवाब अब जनता अपने तरीके से दे रही है। नयी पीढ़ी की रचनात्मकता देखकर भाजपा आईटी सेल अब सकते में है कि किस तरह मोदी विरोधी नारों का जवाब दे। जंतर-मंतर पर अब कॉकरोच जनता पार्टी तक भी बात सीमित नहीं रह गई है। अभिजित दिपके तो गुरुवार को बीमारी का हवाला देकर जंतर-मंतर से अनुपस्थित रहने की बात कह चुके हैं और इसके लिए माफी भी मांग ली, इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने राहुल गांधी की आलोचना इस बात के लिए की कि वे प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने क्यों गए। उन्होंने इसे अगंभीर काम बताया। पहले सोनम वांगचुक खुद शिकायत कर चुके हैं कि राहुल जंतर-मंतर नहीं आए। आम आदमी पार्टी भी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। इन बातों से यह संदेह और पु ता होता है कि राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज आंदोलन जो छेड़ा था, उससे सरकार को तकलीफ हो रही थी और विपक्ष को कमजोर करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी को आंदोलन करने दिया गया। इस आंदोलन के कारण ही बड़ी सं या में लोग जंतर-मंतर पर जुटे भी, लेकिन अब आंदोलन की बागडोर पूरी तरह स्वतस्फूर्त उमड़ी जनता के हाथों में ही दिख रही है। मंच पर कौन से राजनैतिक दल के नेता या कौन सी मशहूर हस्ती पहुंच रही है, दिपके कहां हैं, ये सारी बातें अब आंदोलनकारियों के लिए मायने नहीं रख रहीं। वे व्यवस्था में पसर चुकी गंदगी को दूर करने के लिए खुद ही आगे आ रहे हैं और पर्याप्त अनुशासन बनाए हुए हैं। बेशक कुछ असामाजिक तत्व इनके बीच पहुंच कर माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं, लेकिन गनीमत है कि सब कुछ नियंत्रण में है, यही भारतीय जनता का कमाल है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि छात्रों को इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा, वो चुप नहीं बैठेंगे। विपक्ष से घबराई सरकार अब अपने बचाव में उसे ही दोषी ठहरा रही है। धर्मेन्द्र प्रधान का ट्वीट, जे पी नड्डा की प्रेस कांफ्रेंस सब में राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं।

नए श्रम सुधारों से आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

एन. बाजपयी

नई श्रम संहिताएं कई तरीकों से उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। समेकित संहिताएं औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करेंगी। इसमें रोजगार अनुबंध जारी करना अनिवार्य है। एकल पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न की व्यवस्था है जिससे %व्यापार करने में आसानी होगी तथा नौकरशाही की देरी कम होती है। अनुपालन बोझ को कम करने से कंपनियों को व्यावसायिक गतिविधियों और कम लागत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। भारतीय श्रम बाजार में एक विरोधाभास है। यह एक अत्यधिक संरक्षित औपचारिक क्षेत्र है जो पुरातन और जटिल कानूनों, नियमों व विनियमों द्वारा शासित होता है; और एक बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र नियोक्ताओं की सनक के प्रति संवेदनशील होता है। नियामक व्यवस्था ने सही भूमिका न निभा कर विनिर्माण क्षेत्र के विकास और वृद्धि और कर्मचारी कल्याण दोनों को दोहरी मार लगाई है। इससे भारत लंबे समय से प्रभावित है।

उत्पादक क्षमता में वृद्धि से आर्थिक विकास प्रेरित होता है जो पूंजी संचय, तकनीकी प्रगति और श्रम बल के योगदान से निर्मित होता है। इसमें श्रम एक सक्रिय घटक है जो अन्य संसाधनों के योगदान को कई गुना बढ़ा देता है। श्रम बल के सर्वोतम योगदान के बिना पूंजी और प्रौद्योगिकी जैसे अन्य संसाधनों का कम उपयोग होता है जिससे उप-इष्टतम मूल्य का निर्माण होता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारत की श्रम उत्पादकता लगभग 8 डॉलर प्रति श्रम घंटे है जबकि लक्जमबर्ग में 146 (वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान), आयरलैंड में 143, नॉर्वे में 93 और सिंगापुर में 74 है। जी-20 देशों में भारत सबसे निचले पायदान पर है। यहां तक कि मध्यम आय वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी प्रति घंटे अधिक उत्पादन उत्पन्न करती हैं जो भारत की तुलना में कई गुना अधिक है।

इसके अलावा विश्व स्तर पर भारत प्रति सप्ताह 46-48 घंटे काम करने वाले शीर्ष देशों में से एक है जो चीन और जापान से भी अधिक है। फिर भी बहुत कम मजदूरी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रति श्रमिक उत्पादन बेहद कम होने के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे देशों में प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में हमारे उद्योग असमर्थ हैं। इसी पृष्ठभूमि के मद्देनज़र हमें नवंबर 2025 में मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए बहुत जरूरी श्रम सुधारों को देखना चाहिए। पुराना नियामक ढांचा बेहद जटिल और अप्रचलित था जो 29 खंडित श्रम कानूनों से घिरा और ब्रिटिश राज एवं स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों से शुरू हुआ था। 1,436 प्रावधान, 181 फॉर्म, आठ अलग-अलग पंजीकरण और 31 रिपोर्टिंग आवश्यकताएं थीं जो बहुत बोझिल और कुछ मामलों में असंगत थीं। जटिलता के कारण व्यापार करने में असहजता पैदा हुई, औपचारिक रूप सीमित हो गया और कार्यबल के बड़े हिस्से को सुरक्षा नेट के बिना छोड़ दिया गया। खंडित श्रम कानूनों की श्रृंखला को अब चार आधुनिक और सरलीकृत श्रम संहिताओं में समेकित किया गया है- वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (2020) और जो 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई है। ये सुधार अनुपालन को सरल बनाकर, परिभाषाओं को मानकीकृत कर, कवरेज का विस्तार और गिग इकानॉमी सहित आधुनिक कार्यबल की वास्तविकताओं के साथ नियमों को संरेखित करके एक संरचनात्मक बदलाव लाते हैं। नए कोड, श्रम नियमों के कार्य करने के तरीके को बदल देंगे। इन नियमों के कारण श्रमिकों की सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ाने के बीच संतुलन बनाने की उ मीद है। नई श्रम संहिताएं कई तरीकों से उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। समेकित संहिताएं औपचारिक रोजगार को प्रोत्साहित करेंगी। इसमें रोजगार अनुबंध जारी करना अनिवार्य है। एकल पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न की व्यवस्था है जिससे %व्यापार करने में आसानी% होगी तथा नौकरशाही की देरी कम होती है। अनुपालन बोझ को कम करने से कंपनियों को व्यावसायिक गतिविधियों और कम लागत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। रोजगार को औपचारिक रूप देने से जनशक्ति नियोजन एवं बेहतर उपयोग की सुविधा मिलती है। अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत के कठोर श्रम कानूनों, विशेष रूप से कपड़ा, चमड़ा एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों में गंभीर अड़चन मानते हैं। इसलिए उन्होंने वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों में काम करना पसंद किया। ये सुधार एक पूर्वानुमानित, सुव्यवस्थित वातावरण का संकेत देते हैं जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अधिक प्रवाह को प्रोत्साहित करेगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और भविष्य निधि के तहत असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए चिकित्सा देखभाल, बीमारी नकद लाभ, मातृत्व कवर तथा विकलांगता सहायता के लाभों का विस्तार एक ऐतिहासिक बदलाव है। वाणिज्य दिग्गजों द्वारा उद्योग की पैरवी के बावजूद 10 मिनट के वितरण मॉडल के खिलाफ सरकार का हालिया स्पष्ट रुख इंगित करता है कि श्रमिकों की रक्षा करने की उसकी इच्छा वास्तविक और गंभीर है।

कार्यस्थल सुरक्षा व स्वास्थ्य मानक के तहत विनियमित काम के घंटे, सुरक्षात्मक सुविधाओं तथा लैंगिक समानता मानदंडों के साथ अनिवार्य स्वास्थ्य जांच जैसे नियमों से काम करने की स्थिति में सुधार होगा, कार्यबल का मनोबल बढ़ेगा और इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। ये सुधार महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति देते हैं। इसके लिए यह शर्त रखी गयी है कि वहां सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हों। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर माना जाएगा। औद्योगिक संबंध संहिता विशेष रूप से विनिर्माण, हास्पिटैलिटी तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राईजेस-एमएसएमई) में दशकों पुराने, जटिल नियमों को नेविगेट किए बिना आवश्यकता के अनुसार कार्यबल के स्तर को काम पर रखने एवं समायोजित करने में लचीलापन प्रदान करती है। यह लचीलापन उद्यमों को बाजार की गतिशीलता पर तेजी से प्रतिक्रिया देने, कार्यबल के आकार को समायोजित करने और लाभप्रद रूप से संचालन चलाने में मदद करेगा। यद्यपि यह नियम केवल तभी लागू होता है जब उद्यम में 300 या उससे कम कर्मचारी हों। राज्यों को निचले और उच्च दोनों स्तरों पर इस नियम को बदलने का अधिकार दिया गया है। औद्योगिक पैमाने पर बड़े विनिर्माण, प्रसंस्करण व अर्थव्यवस्थाओं को लॉजिस्टिक्स का लाभ दिलाने के लिए उच्च मात्रा में उत्पादन, स्वचालन और उन्नत प्रौद्योगिकी का फायदा उठाते हैं। बंधे हुए हाथों वाली पुरानी व्यवस्था ने भारत में कपड़ा, चमड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया। औद्योगीकरण तथा बड़ी सं या में नौकरी चाहने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और ओडिशा जैसे राज्य इस सीमा को 300 से बढ़ाकर 30 हजार या 3 लाख तक कर सकते हैं ताकि बड़े पैमाने पर कंपनियों की स्थापना की जा सके। इन राज्यों के हजारों बेरोजगार नौकरियों की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वर्तमान में अधिकांश रोजगार, चाहे राज्यों में हों या प्रवासी स्थानों पर, अनौपचारिक उद्यमों में लगे हुए हैं जहां नौकरी की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, कम मजदूरी दी जाती है, कोई सुरक्षा जाल नहीं है और दंड के भय के बिना %हायर एंड फायर% की नीति अमल में लाई जाती है। संभावित लाभों के बावजूद ट्रेड यूनियनों ने यह तर्क देते हुए सुधारों की आलोचना की है कि रोजगार में लचीलेपन से कार्यबल का अनौपचारिकीकरण या नियमित श्रमिकों की आकस्मिक/अस्थायी आधार पर पुनर्नियुक्ति होगी। (एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्थायी और सुरक्षित नौकरियों को अस्थायी, संविदा या दैनिक आधार के कामों में बदल दिया जाता है।) कार्यबल के रैंक और फाइल के बीच असुरक्षा की शुरुआत होगी एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को नष्ट कर दिया जाएगा। वास्तव में, श्रम जुड़ाव को औपचारिक रूप देने से नौकरी की सुरक्षा में सुधार होगा और श्रमिकों व उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। सरकार को ट्रेड यूनियनों से चर्चा करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे- कुछ ऐसा जो अभी तक नहीं हुआ है। ज़्यादा जानें ब्रेकिंग न्यूज़ सेवा स्थानीय उत्पाद प्रचार बॉलीवुड समाचार पत्रिका यदि ऐसा किया जाता है तो ये सुधार भारतीय आर्थिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में खड़े होंगे। आर्थिक असर बहुआयामी होगा। यह विनिर्माण को बढ़ाने, वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने, असंगठित क्षेत्र को औपचारिक रूप देने तथा विवेकाधीन खर्च बढ़ाने का वादा करता है और यदि इसे स ती से लागू किया जाता है तो ये निर्विवाद रूप से बड़ी सं या में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, उत्पादकता में सुधार करेंगे तथा कर्मचारियों के लिए सुरक्षा नेट प्रदान करते हुए बड़े, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यमों का निर्माण करेंगे। जीडीपी ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान काफी बढ़ेगा। (लेखक सेबी और एलआईसी के पूर्व अध्यक्ष हैं।

बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने के संकेत

नित्य चक्रवर्ती

भारतीय विदेश मंत्रालय में अनुभवी राजनयिक हैं। इसलिए यह देखकर अच्छा लगा कि विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने मंगलवार को ही तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के दिन जमात नेता शफीकुर रहमान से बहुत चुपचाप मुलाकात की। यह सबसे अहम मीटिंग थी क्योंकि भारत के विदेश सचिव उस आदमी को जानते थे जो भारत-बांग्लादेश रिश्तों का रास्ता तय करने में असली शक्ति का इस्तेमाल करेगा और इसलिए उसे लाड़-प्यार करना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को व्यक्तिगत संदेश भेजकर सही कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि %आपकी जीत बांग्लादेश के लोगों के आपके नेतृत्व पर दिखाए गए भरोसे और विश्वास का सुबूत है और देश को शांति, स्थिरता और खुशहाली के रास्ते पर आगे ले जाने के आपकी दृष्टि के लिए उनका जनादेश है। यह जनादेश की वैधता और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने में बीएनपी की अगुवाई वाली सरकार के नए प्रधान मंत्री की भूमिका पर बांग्लादेशियों के भरोसे का एक तरह से समर्थन है।

यह साफ़ है कि इस समय, भारत सरकार के पास नई बीएनपी सरकार के साथ पूरी तरह से आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और प्रधानमंत्री रहमान सबसे अच्छा दांव हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि अभी तारिक रहमान के पास शेख हसीना को भारत से ढाका वापस भेजने के मुद्दे को न्यायाधिकरण और फिर अदलत के आदेश के मुताबिक, और चुनाव प्रचार के दौरान बीएनपी के वादे के मुताबिक, ज़ोर-शोर से उठाने के अलावा कोई चारा नहीं है।

बीएनपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात बहुत जोश में भरी जमात-ए-इस्लामी है, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके गठबंधन में 77 सीटें हैं और जो प्रधानमंत्री तारिक के भारत के पक्ष में उठाए गए हर कदम का इस्तेमाल यह प्रचार करने के लिए करेगी कि तारिक हसीना के रास्ते पर जा रहे हैं। भारत उन्हें बांग्लादेश के हितों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए तारिक के हाथ बंधे हुए हैं। अगर वह भारत के प्रति दोस्ताना रवैया भी चाहते हैं, तो उन्हें अपनी बांग्लादेश वफ़ादारी की परीक्षा पास करनी होगी क्योंकि जमात वहां की संसद और बाहर सड़कों पर, दोनों जगह उनकी गर्दन पर सवार है, जो बांग्लादेश की राजनीति में सरकारों की किस्मत तय करती है।

भारतीय विदेश मंत्रालय में अनुभवी राजनयिक हैं। इसलिए यह देखकर अच्छा लगा कि विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने मंगलवार को ही तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के दिन जमात नेता शफीकुर रहमान से बहुत चुपचाप मुलाकात की।

यह सबसे अहम मीटिंग थी क्योंकि भारत के विदेश सचिव उस आदमी को जानते थे जो भारत-बांग्लादेश रिश्तों का रास्ता तय करने में असली शक्ति का इस्तेमाल करेगा और इसलिए उसे लाड़-प्यार करना होगा। यह पता नहीं है कि जमात नेता ने क्या प्रतिक्रिया दी, लेकिन भारत के अधिकारियों के लिए, जमात के साथ यह बातचीत राजनयिक प्रक्रिया का हिस्सा होनी चाहिए अगर भारत सच में द्विपक्षीय रिश्तों में जल्दी सुधार चाहता है। आखिर बांग्लादेश से लगी भारतीय सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए जमात की भूमिका का इतना महत्व क्यों है? यह इस बात में अन्तर्निहित है कि 12 फरवरी को बांग्लादेश के सभी सीमावर्ती जिलों में हुए चुनावों में, जमात ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे भारत के गृह मंत्रालय के अधिकारियों, खासकर पूर्वी इलाके के बीएसएफ अधिकारियों में डर पैदा हो गया है। बांग्लादेश के खुलना, राजसाही, तथा रंगपुर जिलों, जो पश्चिम बंगाल से लगते हैं, में जमात ने जीत हासिल की है। जैसे, खुलना में, जमात को 36 में से 25 सीटें मिलीं। इन सीमावर्ती जिलों में बहुत सारे भारत-विरोधी तत्व सक्रिय हैं, जिनमें बागी भी शामिल हैं, जिन्हें बीएनपी-जमात राज के दौरान जमात ने पनाह दी थी। शेख हसीना ने 2009 के बाद इसे रोक दिया। असल में,बाद में जमात को काम करने की इजाज़त नहीं दी गई, और उसके विदेशी फंड पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब सीमावर्ती ज़िलों पर पूरा कब्ज़ा होने के कारण, जमात के गुंडे तत्वों को खुली छूट मिलेगी, जब तक कि उन्हें ऊपर से रोका न जाए। यह बीएनपी सरकार और जमात नेतृत्व, दोनों स्तरों पर किया गया है। भारत सरकार जमात के साथ करीबी तालमेल रखकर इसे बेहतर तरीके से ठीक कर सकती है। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जिन पर बिलकुल भी बात नहीं होती। बांग्लादेश संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है जो इस्लाम को राज्य का धर्म भी मानता है। 18 करोड़ आबादी में से लगभग 17 करोड़ मुस्लिम हैं और लगभग एक करोड़ अल्पसं यक, जिनमें ज़्यादातर हिंदू हैं। दूसरे इस्लामिक देशों की तरह, बांग्लादेश में हमेशा कट्टरपंथियों का एक ग्रुप रहता है। जमात में कई समझदार लोग हैं जो अल्पसं यकों के प्रति समझदार हैं।

साथ ही, कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जो कट्टर हिंदू विरोधी और भारत विरोधी हैं। भारत में, हमारा एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। कोई सरकारी धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े भाजपा के कुछ लोग मुसलमानों के कट्टर विरोधी हैं, जबकि भारत की आबादी में मुसलमानों की सं या 14प्रतिशत से ज़्यादा है।

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद पिछले अठारह महीनों में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधिकारियों ने बहुत सारी गलतियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान डॉ. यूनुस के द्विपक्षीय वार्ता के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय प्रधानमंत्री ने डॉ. यूनुस से मिलने से बचने के लिए जानबूझकर न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र आम सभा में भाग लेने का अपना समय बदल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेशियों को दीमक कहा। इन सभी गलतियों ने बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनाओं को और बढ़ा दिया। बांग्लादेश में पहले भारत के समर्थक लोग भी भारत-विरोधी हो गए। आखिर में, मोदी सरकार ने बीसीसीआई को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खेलने से रोकने के फैसले के लिए उकसाया। आईपीएल में भारत-विरोधी भावनाओं को और भड़काया गया। मोदी सरकार को कुछ और समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, भले ही अब अचानक प्रधानमंत्री तारिक को गले लगाने के लिए हद पार कर रहे हैं, जैसा उन्होंने अपने शुरुआती प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में पाकिस्तान के नवाज शरीफ के साथ किया था। बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारना एक लंबा और मुश्किल सफर होगा। भारतीय अधिकारियों को बीएनपी नेता और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक और विपक्षी जमात नेता शफीकुर रहमान दोनों को मनाना होगा साथ ही, भारत को यह पक्का करना चाहिए कि शेख हसीना के प्रत्यार्पण को छोड़कर दूसरे मामलों पर बातचीत रिश्ते सुधारने के लिए सही मायने में शुरू हो। खासकर, आर्थिक मुद्दों पर अब ध्यान देना चाहिए। हसीना मुद्दे में लंबा समय लगेगा और आर्थिक मदद से ठीक होने की प्रक्रिया शुरू करके, भारत हसीना के प्रत्यार्पण के मुद्दे पर सही समाधान के लिए आधार बना सकता है। भारत को बीएनपी और जमात दोनों को यह तरीका अपनाने के लिए मनाना होगा।

विविध समाचार

पंजाब विधानसभा में मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर घमासान, सत्ता पक्ष और विपक्ष हुए आमने–सामने

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मंत्री और सत्तारूढ़ दल के विधायक विपक्ष के नेता को ललकारते हुए सदन के वेल तक पहुंच गए, जिसके बाद कुछ समय तक दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक जारी रही। दरअसल कांग्रेस विधायक ज्तपचज त्ंरपदकमत ैपदही ठंरूं ने स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा कि मौजूदा सरकार ने पंजाब में अब तक कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बाजवा ने कहा कि उनका सवाल केवल सरकार द्वारा बनाए गए मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा था। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर भी सरकार के सहयोग से ही मेडिकल कॉलेज बनाता है। मंत्री ने यह भी दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेजों में 900 से अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के लगभग 40 वर्षों के शासनकाल में भी इतने कॉलेज और सीटों का विस्तार नहीं हुआ था। इस बयान पर विपक्ष के नेता च्तंजंच ैपदही ठंरूं ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में बने मेडिकल कॉलेजों को अपनी उपलब्धि बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में कितने मेडिकल कॉलेज सीधे सरकारी पहल पर स्थापित किए गए हैं। अपने मंत्री का बचाव करने के लिए पार्टी प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा जब बीच में बोलने लगे तो प्रताप सिंह बाजवा ने एतराज किया कि वह किस कैपेसिटी में जवाब दे रहे हैं। वह ना तो मुख्यमंत्री हैं और ना ही स्वास्थ्य मंत्री। इस पर स्पीकर ने कहा कि सरकार में सभी मंत्रियों की जवाबदेही होती है। इस पर उन्होंने स्पीकर पर हाउस को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नहीं, अगर मंत्री को जवाब नहीं आ रहा है तो केवल मुख्यमंत्री ही हस्तक्षेप कर सकते हैं जबकि यहां पर स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके पास जवाब भी है तो वह ही जवाब दें। इस दौरान पर वह अमन अरोड़ा को अपशब्द भी बोल गए जिस पर अरोड़ा ने कहा कि वह यह बर्दाशत नहीं करेंगे। वह विपक्ष के नेता का आदर करते हैं लेकिन इस तरह की शब्दावली को कतई बर्दाशत नहीं किया जाएगा ।इस दौरान स्पीकर ने नियम भी पढ़ कर सुनाए तो भी बाजवा नहीं माने। तब तक वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जो अभी तक सदन में नहीं थे, आ गए और उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा की ओर से बोली गई शब्दावली पर सख्त एतराज किया और ललकारते हुए सदन में आ गए दोनों ओर से तू तू, मैं मैं में शुरू हो गई।

'ईरान–इजराइल संघर्ष के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित'

चंडीगढ़। श्री गुलाब चंद कटारिया, पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक की अध्यक्षता में शहर की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम तथा चल रहे ईरानदृइजराइल संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन की तैयारियों और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई। प्रशासक को अवगत कराया गया कि उपायुक्त, यूटी चंडीगढ़ द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी कर अनुरोध किया गया है कि यदि चंडीगढ़ का कोई निवासी वर्तमान में युद्ध प्रभावित एशियाई देशों में फंसा हुआ है, तो उसके परिजन या परिचित तुरंत उपायुक्त कार्यालय को इसकी जानकारी दें। यह जानकारी कार्यालय में आकर अथवा ईमेल कब–बीक/nic-in के माध्यम से साझा की जा सकती है, जिसमें संबंधित व्यक्ति का नाम, पासपोर्ट नंबर (यदि उपलब्ध हो), वर्तमान देश व शहर, संपर्क विवरण तथा चंडीगढ़ में रहने वाले परिजनों का विवरण शामिल हो, ताकि प्रशासन आवश्यक समन्वय कर सहायता एवं राहत प्रदान कर सके। बैठक के दौरान प्रशासक ने शहर में तेल एवं ईंधन सहित आवश्यक वस्तुओं की उपलब्ध ता की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि यूटी चंडीगढ़ में इन वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और शहरवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। अंतरराष्ट्रीय स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रशासक ने कहा कि कुछ स्थानों पर चल रहे संघर्ष के कारण एलपीजी गैस की संभावित कमी को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। श्री कटारिया ने जोर देते हुए कहा कि तेल, ईंधन या एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी या कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को कड़ी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीमों का गठन किया गया है, जो शहर के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर जमाखोरी रोकने तथा आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी।

पंजाब में महिलाओं को निशाना बनाकर पैसे वसूलने वाले साइबर धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश, 3.49 लाख रुपये, 500 डॉलर समेत तीन गिरफ्तार

चंडीगढ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पंजाब पुलिस के स्टेट साइबर क्राइम डिवीजन ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सोशल मीडिया पर महिलाओं के नाम से फर्जी पहचान बनाकर अनजान लोगों से धोखाधड़ी करने और उनसे पैसे वसूलने वाले अंतरराज्यीय रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अभिषेक भार्गव, आकाश भार्गव उर्फ अमन और लक्की भार्गव के रूप में हुई है। ये तीनों राजस्थान के झुंझुनू के निवासी हैं और आपस में सगे भाई हैं। फिलहाल ये मोहाली के सेक्टर–70, एसएएस नगर(मोहाली) में रह रहे थे। पुलिस टीमों ने उनके कब्जे से 3.49 लाख रुपये नकद, 500 अमेरिकी डॉलर, 29 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक डोंगल, एक टैबलेट और मोबाइल फोन के 38 खाली डिब्बे बरामद किए हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपियों ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के नाम से फर्जी प्रोफाइल बना रखे थे और इनके माध्यम से अपने टारगेट से संपर्क करते थे। उन्होंने बताया कि आरोपी अपने टारगेट, खासकर महिलाओं का विश्वास जीतने के लिए महिलाओं जैसी आवाज निकालने हेतु वॉयस–चेंजिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद वे पीडिघ्तों के एआई द्वारा तैयार किए गए आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलते थे। इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम वी. नीरजा ने बताया कि एक पीडिघ्ता के पिता की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। पीडिघ्ता के साथ वर्ष 2023 से 2025 के बीच लगभग 3.10 लाख रुपये की ठगी की गई थी, जब वह कनाडा में रह रही थी। उन्होंने बताया कि एसपी जसपिंदर सिंह की निगरानी में स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के एसएचओ अमनदीप सिंह की अगुवाई में की गई जांच में पता चला कि रैकेट का सरगना आकाश भार्गव है, जिसने करीब दो साल पहले यह तरीका तैयार किया था। आरोपी फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर लोगों को निशाना बनाते थे और कभी–कभी नकली ध ाार्मिक गुरु या ज्योतिषी बनकर भी लोगों को ठगते थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने इस तरीके से लगभग 40 लाख रुपये की ठगी की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों और साइबर धोखाधड़ी के अन्य पीडिघ्तों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इस संबंध में एफआईआर नंबर 14 दिनांक 08.08.2025 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) और 61(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, मोहाली में दर्ज की गई है। स्पेशल डीजीपी वी. नीरजा ने सलाह दी कि सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले लोग, खासकर महिलाएं, ऐसे ज्योतिषियों या अन्य व्यक्तियों से सावधान रहें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सहानुभूति या मदद देने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि निजी जानकारी और विवरण किसी भी स्थिति में सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

"बॉटल्स फॉर चेंज" सीएसआर पहल के अंतर्गत पर्यावरण भवन में रीसाइकिल प्लास्टिक बेंचों की स्थापना

चंडीगढ़। सतत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में आज सेक्टर–19 स्थित पर्यावरण भवन में पाँच रीसाइकिल प्लास्टिक बेंच स्थापित की गईं। यह स्थापना Bisleri International Private Limited की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल "बॉटल्स फॉर चेंज" के अंतर्गत की गई। इसका औपचारिक उद्घाटन Saurabh Kumar, आईएफएस, सदस्य सचिव, बेंदकपहंती च्वससनजपवद Control Committee द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में किया गया। ये पर्यावरण–अनुकूल बेंच प्रत्येक लगभग 60 किलोग्राम रीसाइकिल किए गए प्लास्टिक बोतल कैप्स से निर्मित हैं, जो प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण और उसे टिकाऊ सार्वजनिक उपयोग के ढांचे में परिवर्तित करने का एक अभिनव उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

यह पहल जिम्मेदार प्लास्टिक निपटान, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, तथा प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में रीसाइक्लिंग की भूमिका को रेखांकित करती है। स्थापना के अंतर्गत स्थल पर मल्टी–लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स से बना एक रचनात्मक बैकड्रॉप भी प्रदर्शित किया गया, जिन्हें सामान्यतः रीसाइकिल करना कठिन होता है। इस बैकड्रॉप की डिजाइन एक माउथ–टू–फुट कलाकार द्वारा तैयार की गई, जो समावेशिता, रचनात्मकता और अपशिष्ट पदार्थों के जिम्मेदार प्रबंधन से उनके उपयोगी संसाध ानों में रूपांतरण की संभावनाओं का प्रतीक है। इस अवसर पर सदस्य सचिव ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोगात्मक प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहलें न केवल प्लास्टिक कचरे को कम करने में सहायक हैं, बल्कि नागरिकों में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

पंजाब में अशिक्षा, नशे और बेरोजगारी का खात्मा आप सरकार की प्रमुख प्राथमिकता : भगवंत मान

जालंधर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार राज्य में शिक्षा, रोजगार और नशे के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता देते हुए आम लोगों के कल्याण से जुड़ी नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आदमपुर के गाजीपुर मोहल्ला में लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य योजनाओं से लेकर रोजगार सृजन और नशा विरोधी मुहिम तक की पहलों की जानकारी दी। साथ ही पिछली सरकारों पर लोगों के कल्याण और युवाओं के भविष्य की अनदेखी करने की तीखी आलोचना भी की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "आम आदमी कभी भी इन पारंपरिक पार्टियों के एजेंडे में नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमेशा अमीरों के हितों की रक्षा की।" उन्होंने कहा कि आम आदमी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने का श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है और अब पंजाब सरकार आम लोगों के हित में कई नई पहलें कर रही है। सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "आप सरकार जानती है कि संसाध ान कैसे जुटाने हैं और उन्हें प्रभावी तरीके से कैसे उपयोग करना है। आज थर्मल प्लांट खरीदे जा रहे हैं, बिजली मुफ्त दी जा रही है, नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाया जा रहा है, किसानों को नियमित बिजली आपूर्ति मिल रही है और आम लोगों के हित में बिजली दरें कम की जा रही हैं।" उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियाँ पूरी की हैं और लोगों को टोल प्लाजा बंद करने जैसे कई अतिरिक्त लाभ भी मिले हैं। वहीं, उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि नोटबंदी जैसी योजनाओं ने आम लोगों, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से प्रभावित किया। 'मुख्यमंत्री माएँ–धियाँ सत्कार योजना' का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए यह राशि बहुत महत्वपूर्ण है और यह पहल महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस योजना का मजाक उड़ाते हैं या सवाल उठाते हैं, वे आम आदमी के लिए 1000 रुपये के महत्व को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि कुछ अमीर नेता एक समय के भोजन पर ही हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, इसलिए उन्हें यह समझ नहीं आता कि यह सहायता मेहनतकश परिवारों के लिए कितनी अहम है। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं, जहाँ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही हैं। इसके अलावा 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह देश में अपनी तरह की पहली व्यापक स्वास्थ्य कवरेज योजना है। नशों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 'युद्ध नशों विरुद्ध' मुहिम शुरू की है, जिसके तहत नशा तस्करी की सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है और इस अपराध में शामिल लोगों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। पूर्व सरकारों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कई नेताओं ने सत्ता में रहते हुए लोगों का शोषण किया और व्यवसायों में अवैध हिस्सेदारी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नीतियों ने पंजाब को नुकसान पहुँचाया और युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया। शिरोमणि अकाली दल की 'पंजाब बचाओ यात्रा' पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इसका असली नाम "परिवार बचाओ यात्रा" होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अकाली नेताओं को बताना चाहिए कि वे अब पंजाब को किससे बचाने की बात कर रहे हैं।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, गुरूवार 06 अगस्त 2026 | पृष्ठ-6

ओडिशा ने छोटे खनिजों के खनन परमिट के लिए कड़े नियम जारी किए, अधिकारियों को चेतावनी दी

भुवनेश्वर ०५/०८ (संवाददाता): ओडिशा सरकार ने छोटे खनिजों (माइनर मिनरल्स) के लिए खदान परमिट जारी करने की प्रक्रिया पर निगरानी बढ़ा दी है। कई इलाकों में परमिट सिस्टम के कथित गलत इस्तेमाल की खबरें सामने आने के बाद, सरकार ने ज़िला प्रशासन को ओडिशा माइनर मिनरल कंसेशन (संशोधन) नियम, 2025 को सख़्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। 3 अगस्त, 2026 को जारी एक आदेश में, स्टील और माइंस विभाग के अतिरिक्त मुज़्य सचिव देवरंजन कुमार सिंह ने सभी ज़िला कलेक्टरों और ज़िला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि खदान परमिट केवल सरकारी कार्यों और जनहित वाली परियोजनाओं के लिए ही दिए जाएं। निर्देश में कहा गया है कि कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कड़ी जांच होगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने यह कदम उन खबरों के बाद उठाया है जिनमें कहा गया था कि निजी या गैर-सरकारी परियोजनाओं के लिए भी खदान परमिट जारी किए जा रहे थे। विभाग ने ऐसे मामलों की भी पहचान की है जिनमें आवेदकों ने परमिट पाने के लिए खुद को सरकारी परियोजनाओं का प्रतिनिधि बताया था। सरकार ने ऐसी गतिविधियों को मनमाना, गैर-कानूनी और संशोधित नियमों का उल्लंघन बताया है और ज़िला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे आवेदनों को शुरुआती चरण में ही खारिज कर दें।

यह स्पष्टीकरण %ओडिशा माइनर मिनरल कंसेशन (संशोधन) नियम, 2025 के तहत किए गए संशोधनों के बाद आया है। इन नियमों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के महत्व वाले बुनियादी ढांचा कार्यों के लिए छोटे खनिजों की समय पर उपलज़्धता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।

संशोधित व्यवस्था के तहत, गैर-वन क्षेत्रों के लिए खदान परमिट जारी करने का अधिकार माइनिंग ऑफिसर के पास है, जबकि वन भूमि के लिए परमिट संबंधित डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (ष्ठस्नह्र) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

सरकार ने इन परमिटों की अवधि और दायरे को भी स्पष्ट किया है। खदान परमिट या तो पूरी परियोजना की स्वीकृत खनिज आवश्यकता के लिए या काम के किसी खास चरण के लिए जारी किया जा सकता है। इसकी वैधता दो साल या परियोजना या संबंधित चरण के पूरा होने तक (जो भी पहले हो) सीमित है। दो साल की अवधि के बाद भी काम जारी रखने के किसी भी अनुरोध पर राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी लेने के बाद ही विचार किया जा सकता है। संशोधित नियमों के पीछे के उद्देश्य को दोहराते हुए, स्टील और माइंस विभाग ने कहा कि इन उपायों का मकसद सरकारी राजस्व की रक्षा करते हुए सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए छोटे खनिजों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना है। ज़िला प्रशासन को कानूनी प्रावधानों का सज़्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है ताकि परमिट सिस्टम का इस्तेमाल उसके निर्धारित उद्देश्य से बाहर की गतिविधियों के लिए न किया जा सके।

एच.एस.एम.-2 ने नया मासिक रोलिंग रिकॉर्ड बनाया, निदेशक प्रभारी ने टीम की क्षमता की सराहना की

राउरकेला ०५/०८ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के हॉट स्ट्रिप मिल-2 (एच.एस.एम.-2) ने जुलाई 2026 में क्वारयल भार के आधार पर 2,48,598 टन रोलिंग कर अब तक का सर्वाधिक मासिक उत्पादन दर्ज करते हुए एक और महत्वपूर्ण उपलज़्धि हासिल की है। इसने मार्च 2026 में बनाए गए 2,47,994 टन के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उल्लेखनीय है कि एक अन्य उपलज़्धि के रूप में शीट शियरिंग लाइन ने भी जुलाई 2026 में क्वाउयल भार के आधार पर 32,989 टन शीयरिंग कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह जुलाई 2025 में दर्ज 29,917 टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से अधिक है। 3 अगस्त 2026 को आर.एस.पी. के निदेशक प्रभारी, श्री आलोक वर्मा ने मिल परिसर का दौरा कर एच.एस.एम.-2 की पूरी टीम को इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। टीम के साथ विचार-विमर्श करते हुए उन्होंने उनकी प्रभावी योजना एवं परिचालन उत्कृष्टता की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलज़्धि टीम की मजबूत कार्यक्षमता और क्षमता का परिचायक है। उन्होंने आगे कहा, 'मेरा मानना है कि एच.एस.एम.-2 टीम की वास्तविक क्षमता 2.55 लाख टन रोलिंग की है।' अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 'क्षमता वह नहीं है जो हमने हासिल कर ली है, बल्कि क्षमता वह है जिसे हम कभी हासिल नहीं कर सकने योग्य समझते थे।'

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (एच.आर.), श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक (वर्क्स), श्री बिस्व रंजन पलई, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक (माईन्स), श्री एम.पी.सिंह, कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएँ), श्री सुदीप पालचौधरी, मुज़्य महा प्रबंधक (विज़ एवं लेखा), श्री राजेश दासगुप्ता सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी गण्यमान्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए एच.एस.एम.-2 की टीम तथा सहयोगी विभागों को इस शानदार उपलज़्धि के लिए बधाई दी। यह ऐतिहासिक उपलज़्धि स्टील मेल्टिंग शॉप्स, प्रोडज़्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ट्रैफिक एंड रॉ-मटेरियल्स, रिसर्च एंड कंट्रोल लैब्रोटोरी, फील्ड मशीनरी मेंटेनेंस तथा सभी सेंट्रालाइज्डो मेंटेनेंस विभागों के उत्कृष्ट सहयोग एवं आपसी समन्वय से संभव हो सकी। इन विभागों के समन्वित प्रयासों ने परिचालन उत्कृष्टता और उत्पादन दक्षता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

20 लाख की लूट का मास्टरमाइंड भुवनेश्वर पुलिस ने पकड़ा

भुवनेश्वर २३/०५ (संवाददाता):भुवनेश्वर पुलिस ने शिकायत करने वाले के करीबी दोस्त समेत दो लोगों को पहला इलाके के पास 20 लाख रुपये की लूट की साज़िश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में गिरज़्तार किया। सूत्रों के मुताबिक, यह केस तब दर्ज किया गया जब शिकायत करने वाले प्रभात कुमार को घटना के दौरान तलवार से हुए हमले में चोटें आईं। गिरज़्तार किए गए लोगों में सरोज सुतार और बाबुलू बेहरा हैं, जबकि इस क्राइम में शामिल उनके दूसरे साथी अभी भी फरार हैं।

लूट तक का सिलसिला पुलिस ने बताया कि प्रभात ने 24 नवंबर को किसी दूसरे जान-पहचान वाले से लोन के तौर पर लिए गए 20 लाख रुपये निकाले थे। सरोज सुतार, जो पैसे लेने के समय उसके साथ था, ने कथित तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी रकम हड़पने की साज़िश रची। पुलिस ने कहा कि सरोज ने चाय पीने के बहाने प्रभात को जलसा बार के पास रोकने का इंतज़ाम किया। पहले से तय इंतज़ाम के मुताबिक, सरोज के साथियों को लेकर दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, जबकि दोनों बैठे हुए थे। इसके बाद ग्रुप ने कथित तौर पर प्रभात पर तलवार से हमला किया और पूरे 20 लाख रुपये लेकर भाग गए। पुलिस ने अंदर की भूमिका का पता कैसे लगाया, हमले के बाद शिकायतकर्ता के साथ पुलिस स्टेशन जाने के बावजूद, सरोज के बयानों में अंतर था।

जांचकर्ताओं ने इलाके के CCTV फुटेज की डिटेल में जांच की और आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच की। फुटेज और मोबाइल-लोकेशन पैटर्न कथित तौर पर सरोज के दावों के उलट थे और हमलावरों के साथ तालमेल बिठाने का संकेत देते थे। वेरिफिकेशन के बाद, पुलिस ने उसे डकैती की साजिश का मुज़्य साजिशकर्ता बताया और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।

सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने गिरज़्तार आरोपियों से 5.70 लाख रुपये कैश, हमले में इस्तेमाल की गई तलवार और डकैती के दौरान कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल जज़्त की है

क्राइम सीन में शामिल गाड़ियों की मौजूदगी दिखाने वाले कई CCTV फ्रेम सबूत के तौर पर शामिल किए गए हैं। क्राइम लोकेशन के तौर पर पहचाने गए जलसा बार इलाके में काम करने वाले सर्विलांस कैमरे भी थे, जिससे सीक्वेंस को फिर से बनाने में मदद मिली।

भद्रक डकैती के दौरान परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया गया

भद्रक ०५/०८ (संवाददाता): जगदलपुर गांव में लुटेरों ने परिवार को बंधक बनाया, कीमती सामान लूटा . भद्रक ग्रामीण पुलिस स्टेशन के इलाके में जगदलपुर गांव से हथियारबंद डकैती की खबर आई है, जहां बदमाशों के एक गिरोह ने कथित तौर पर बंदूक की नोक पर एक परिवार को बंधक बना लिया। खबर है कि लुटेरे घर से सोने-चांदी के गहने और लाखों रुपये नकद लेकर भाग गए। भागते समय ग्रामीणों ने लुटेरों को रोकने की कोशिश की।बताया जा रहा है कि लुटेरे देर रात एक घर में घुस गए, जब ग्रामीणों ने घर के अंदर से शोर सुना।तभी बदमाशों ने परिवार को बंदूक की नोक पर लिया, कमरों में घुसे और सभी कीमती सामान और गहने लूट लिए।इसके बाद जब बदमाश भागने लगे तो ग्रामीणों ने उनका पीछा किया, काफी मशक्कत के बाद एक हमलावर को पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और फिर स्थानीय पुलिस को सूचना दी। बाकी बदमाश मौके से भाग निकले। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

कांजीपानी घाट में बस पलटी, यात्रियों की बाल-बाल बची जान

बांसपाल ०५/०८ (संवाददाता):केंदुझार ज़िले के कांजीपानी घाट में एक बस के पलटने से उसमें सवार 30 लोगों की जान बाल-बाल बची।बस कालियाहाटा से केंदुझार जा रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंदुझार जाते समय बस का नियंत्रण बिगड़ गया और वह कांजीपानी घाट में पलट गई। हादसे की वजह से बस का अगला और साइड का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, एक बड़ा हादसा टल गया ज़्योंकि बस गनीमत रही कि गहरी खाई में नहीं गिरी। हादसे की सूचना मिलने पर कांजीपानी पुलिस मौके पर पहुंची और बस को सड़क से हटाया। इसके बाद घायल यात्रियों को निकालकर इलाज के लिए पास के अस्पताल भेजा गया।पुलिस उन हालात की जांच कर रही है जिनमें बस का संतुलन बिगड़ा और हादसे की असल वजह ज़्या थी।

मयूरभंज में खड़ी कार के अंदर पुलिस कॉन्स्टेबल मृत मिला, पुलिस ने जांच शुरू की

मयूरभंज ०५/०८ (संवाददाता): मयूरभंज ज़िले के पद्मनाभपुर में ह॥-18 पर खड़ी एक कार में पुलिस कॉन्स्टेबल मृत पाया गया। मृतक की पहचान झारपोखरियार के रहने वाले बसंत महंता के तौर पर हुई है।रिपोर्ट्स के मुताबिक, कल सुबह 11 बजे से सड़क किनारे एक अनजान कार खड़ी थी। जब वह दोपहर तक वहीं खड़ी रही, तो ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने कार की सीट पर महंता का शव पड़ा देखा। यह देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, कार से शव निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा।बाद में, पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी।कॉन्स्टेबल बसंत महंता की मौत से जुड़े हालात की जांच चल रही है। पुलिस यह भी देख रही है कि ज़्या घटनास्थल पर कोई सुराग मिला है।

आरएसपी में ज़्लास्ट फर्नेस-4 के ज़्लोइंग-इन के साथ परिचालन के नए आयाम की शुरुआत

राउरकेला ०५/०८ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) ने ज़्लास्ट फर्नेस-4 (बीएफ-4) के सफल ज़्लोइंग-इन के साथ परिचालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलज़्धि हासिल की। यह कार्य आरएसपी के निदेशक प्रभारी, श्री आलोक वर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (खान विकास), श्री बी के गिरि, कार्यपालक निदेशक (संकार्य), श्री बी आर पलई, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक (खान), श्री एम पी सिंह, कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएँ), श्री एस पाल चौधरी, मुज़्य महाप्रबंधक प्रभारी (विज़ एवं लेखा), श्री राजेश दासगुप्ता, अनेक मुज़्य महाप्रबंधक, आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारी तथा ज़्लास्ट फर्नेस विभाग एवं सहयोगी एजेंसियों के कर्मचारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि, ज़्लास्ट फर्नेस-4 ने 8 सितंबर, 2020 को रिलाइनिंग के बाद अपना छठा अभियान प्रारंभ किया था तथा 5 जुलाई, 2024 को इसे ज़्लो-डाउन किया गया था। इसके बाद विस्तारित शटडाउन अवधि के दौरान फर्नेस में शॉटक्रिटिंग तथा अन्य आवश्यक मरज़्मत कार्य किए गए और जुलाई, 2026 में इसे पुनः संचालन के लिए तैयार किया गया। सफल ज़्लोइंग-इन सूक्ष्म योजना, समन्वित क्रियान्वयन तथा ज़्लास्ट फर्नेस समूह के समर्पित प्रयासों का परिणाम है, जिसमें विभिन्न सहयोगी विभागों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभा को संबोधित करते हुए श्री आलोक वर्मा ने ज़्लास्ट फर्नेस टीम को बीएफ-4 के सुरक्षित, स्थिर एवं सफल परिचालन प्रारंभ होने पर शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा प्रमुख तकनिकी-आर्थिक मानकों के अनुकूलन के माध्यम से हॉट मेटल की उत्पादन लागत कम करने पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से कोक की खपत (कोक रेट) में कमी, पल्वेराईज़्ड कोल इंजेज़्शन (पीसीआई) दर में वृद्धि तथा उच्च हॉट-ज़्लास्ट तापमान प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे फर्नेस के समग्र प्रदर्शन एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सके। श्री बी आर पलई ने ज़्लास्ट फर्नेस टीम तथा सभी सहयोगी विभागों को मरज़्मत एवं पुनः संचालन कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए बधाई दी। उन्होंने सभी टीमों द्वारा प्रदर्शित सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए बीएफ-4 के तकनिकी-आर्थिक प्रदर्शन में निरंतर सुधार के लिए सतत प्रयास करने का आह्वान किया। ज़्लास्ट फर्नेसेस के मुज़्य महाप्रबंधक, श्री सुमीत कुमार ने निदेशक प्रभारी, कार्यपालक निदेशकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने संपूर्ण ज़्लास्ट फर्नेस कर्मीसमूह को इस महत्वपूर्ण उपलज़्धि के लिए बधाई देते हुए विभिन्न सहयोगी विभागों के अमूल्य योगदान की भी सराहना की।